इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नालॉजी एक था, जिसे कि आई.आई.टी. के रूप में विकसित किए जाने की सिफारिश की गई थी। इस नई सरकार के आने के बाद उस सिफारिश पर कुछ खास अमल नहीं हुआ था, लेकिन जुलाई, 2008 में यह फैसला किया गया कि इस देश में कुछ और आई. आई.टी. संस्थान खोले जाएंगे तथा बी.एच.यू. की इस संस्था को आई.टी. के स्थान पर आई.आई.टी. के रूप में विकसित किया जाएगा। बड़े खेद से कहना पड़ता है कि जिन अन्य संस्थानों की सिफारिश की गई थी, उनके बारे में तो कार्यवाही की गई, लेकिन इस बी.एच.यू. की आई.टी. के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई। यह एक अजीव गोरखधंधा है, जो सामान्य सी क्रिया के द्वारा किया जा सकता था। केवल एक वैधानिक संशोधन करने की जरूरत थी कि अब यह संस्था आई.आई.टी हो गई है, लेकिन इतना भी नहीं किया गया और आज परिणाम यह है कि सारे बी.एच.यू. के छात्र उद्वेलित हैं। आई.आई.टी. के सैकड़ों छात्र दिल्ली में आए हुए हैं। बहुत दिनों तक उन्होंने वहंा धरने दिए हैं और अब यह असंतोष न केवल बी.एच.यू. में बल्कि बनारस की अन्य शिक्षा संस्थानों में और मुझे आशंका है, जो लक्षण मुझे दिखाई दे रहे हैं कि सारे पूर्वांचल में इस असंतोष की आग उठेगी और तब सारा शैक्षिक सत्र भी ध्वस्त हो जाएगा। मैं ऐसा समझता हूं कि सरकार ने इस पर तत्काल ध्यान देना चाहिए। हमने तो यहां तक कहा था कि अगर उस वैधानिक उपाय को बरतने के लिए कोई सरकार इस प्रकार का संशोधन अभी भी लाती है, जो आई. आई. टी. का विधेयक है, उसमें तो हम उसकी मदद करेंगे, क्योंकि यह एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ है, यह संस्था इस देश की सबसे पुरानी आई. टी. है और मैं यह इस सदन को बताना चाहूंगा कि आज़ादी के बाद अगर यह संस्था न हुई होती, तो आज़ादी के बाद इस देश में टेक्नालॉजी, बिजली के मामले में, मेटलर्जी के मामले में, रसायन के मामले में और बहुत कुछ अन्य क्षेत्रों में भी इस देश में हाहाकार मचा होता। यह मदन मोहन मालवीय जी की दूरदृष्टि थी कि उन्होंने एक ऐसी संस्था का निर्माण किया और आज़ादी के बाद 1947 से 1970-75 तक इस देश की अधिकांश टेक्नीकल संस्थाएं और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये सब के सब इसी संस्था के छात्रों के द्वारा नियंत्रित और नियमित किए गए थे। इसलिए मेरा सरकार से यह अनुरोध है और मैं यह चाहूंगा कि इस पर तत्काल कार्यवाही की जाए और उन छात्रों के भविष्य को बिगड़ने से रोका जाए, अन्यथा यह असंतोष सारे उत्तर प्रदेश के शैक्षिक सत्र को ध्वस्त करेगा, मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर अपना response जल्दी दे।

Dismay over Disinvestment of PSU Shares

SHRI TAPAN KUMAR SEN (West Bengal) : Sir, I rise to express my concern over the renewed move of the Government to start disinvestment in the profitable public sector. Only one day before, in Lok Sabha, and also in this House, while commending the Budget, the hon. Finance Minister spoke quite high of the role of the public sector in stabilising and protecting the national economy, in the background of the severe global financial crisis. But, immediately after that commendment made in Budget, on the next day, as reported by the Press, the Government is again planning to offload shares of the profitable public sector in the market. That is totally against the national interest and particularly so, when the stock market is sinking.

The prices are going down, and at this time, this renewed initiative to sell out the shares of the profitable public sector means handing over the control of the public sector units to private hands at throw away prices because now the prices are sinking, and this is all the more dangerous particularly

when the public sector companies are also having different other routes to raise money through bonds and debentures, and in the changed financial circumstances, common people are having more faith on the bonds and debentures issued by the public sector. So, it is not just necessary that the equity route has to be adopted by the public sector to raise funds. So, from all logic, this is completely illogical proposition to go in for offloading shares of the public sector, and through you, Sir, I urge upon the Government not to resort to such a dangerous exercise which will finally mean a total fraud of a different type on the national economy and the people of the country.

SHRIMATI BRINDA KARAT (West Bengal) : Sir, I associate myself with this.

SHRI MATILAL SARKAR (Tripura) : Sir, I also associate myself with this.

SHRI MOINUL HASAN (West Bengal) : Sir, I also associate myself with this.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Now, we will take up the Motion of Thanks. Shri Jai Parkash Aggarwal.

SHRIMATI BRINDA KARAT : Sir, is there no lunch break today?

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Lunch break is there at 1 O'clock...*(Interruptions)*... Still 20 minutes are there.

SHRI S.S. AHLUWALIA (Jharkhand) : Sir, no senior leader is present here.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : I am not insulting you. Normally, the practice is, the Leader of the other House should be present in this House when this is taken up...*(Interruptions)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Discussion is going on in the other House.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL) : It is simultaneously being discussed in both the Houses. After the hon. Leader of the Opposition has spoken there, the hon. Minister for External Affairs would come here.

SHRI SITARAM YECHURY (West Bengal) : Let us begin in his presence. When the hon. Minister for External Affairs would come here.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, I appreciate your view. But the time at our disposal is very short ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : But the point is, how do we use our 15 minutes? Do we take these 15 minutes for lunch? Do we take these 15 minutes for lunch?

SHRI SITARAM YECHURY : Sir, please permit me to speak on the Satyam scam. I will make very good use of the time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : No, no. We will adjourn for one hour.

2.00 P.M.

The House is adjourned till 2 o'clock.

The House then adjourned for lunch at forty-three minutes past twelve of the clock.

The House reassembled after lunch at two minutes past two of the clock, MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (**राजस्थान**) : माननीय उपसभापति महोदय, ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : यह अंतरिम बजट है, इसको रख लेने दो।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं रखने से पहले कुछ कहना चाहता हूं। ...(**व्यवधान**)... मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भाषण हुआ ही नहीं।

श्री उपसभापति : कौन सा भाषण।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अभिभाषण।

श्री उपसभापति : अभी नहीं।

THE INTERIM BUDGET (JHARKHAND), 2009-2010

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL) : Sir, I beg to lay on the Table a statement (in English and Hindi) of the estimated receipts and expenditure of the State of Jharkhand for the year 2009-2010. [Placed in Library. *See* No. L.T. 10517/09]

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (JHARKHAND) 2008-2009

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL) : Sir, I beg to lay on the Table a statement (in English and Hindi) showing the Supplementary Demands for Grants (Jharkhand) for the year 2008-2009. [Placed in Library *See* No. L.T. 10518/09]

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Shri Jai Prakash Aggarwal...*(Interruptions)*... Please move the Motion ...*(Interruptions)*...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (राजस्थान) : माननीय उपसभापति महोदय, धन्यवाद प्रस्ताव पर मूव करने के लिए आपने इजाजत दी है। मैं पोइंट ऑफ् आर्डर उठाना चाहता हूं।

श्री उपसभापति : बताइए।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपसभापति महोदय, यह बात सच है कि 12 फरवरी, 2009 को संयुक्त अधिवेशन में माननीया राष्ट्रपति महोदया ने अभिभाषण किया और उस पर धन्यवाद प्रस्ताव आपकी अनुमति से जायसवाल जी ला रहे हैं। किंतु मेरा यह कहना है कि वह अभिभाषण अभिभाषण ही रहे, मैं आपके सामने विधान को कोट करना चाहता हूं।

श्री उपसभापति : आपका पाइंट ऑफ् आर्डर क्या है, वह तो बताइए।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वही तो बतला रहा हूं।